भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2298
जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को टेक ओवर करना

2298. श्री इलामारम करीम:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास केरल राज्य सरकार से इंस्ट्रूमेंटेंशन लिमिटेड, पलक्कड़ को टेक ओवर करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उस भूमि की कीमत पूछने के क्या कारण हैं, जो केरल राज्य सरकार से मुफ्त में प्राप्त हुई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (घ): केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 30.11.2016 को इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा यूनिट के बंदीकरण को अनुमोदित किया और केरल सरकार (जीओके) को इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पलक्कड़ यूनिट के हस्तांतरण हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया। केरल सरकार ने हस्तांतरण की पद्धतियाँ तैयार करने के लिए केरल सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, भारी उद्योग विभाग ने समिति में प्रतिनिधित्व किया। इस समिति के विचार-विमर्शों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक गोइंग कन्सर्न के रूप में केरल सरकार को पलक्कड़ यूनिट के हस्तांतरण की पद्धतियों को परिभाषित करते हुए दिनांक 16.11.2018 को भारत सरकार, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), केरल सरकार, उद्योग विभाग द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, जब पलक्कड़ यूनिट की निवल सम्पत्ति मूल्य (एनएवी) का अपेक्षित आंकलन किया जा रहा था, तब यह देखा गया कि उच्च स्तरीय समिति ने पलक्कड़ यूनिट के अधिकार वाली 566.30 एकड़ भूमि के मूल्य पर विचार नहीं किया जिसे दिनांक 30.03.1964 की औद्योगिक उद्देश्यों हेतु सरकारी भूमि निर्धारण नियमावली के तहत पुदुस्सेरी, केरल में प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंटेशन परियोजना की स्थापना के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को रजिस्ट्री पर सौंपा गया था, जिसका हस्तांतरण पद्धति पर आर्थिक संबंध है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के स्वामित्व वाली इस भूमि की कीमत का अभी आकलन नहीं किया गया है।

******